

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर- 59/2021

(जी सी एम एस नम्बर 2021/36)

उनवान प्रकरण :-

रघुराज सिंह परमार पुत्र अशोक सिंह परमार जाति ठाकुर निवासी बडा गॉव  
तसीमो तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-राजवीर पुत्र बंगाली | समस्त जातिगण ठाकुर
- 2-ओमशंकर पुत्र श्यामबाबू |
- 3-सन्तोषी पुत्र श्यामबाबू | निवासीगण ग्राम तसीमों
- 4-आशू पुत्र मुकन्द |
- 5-अमित पुत्र मुकन्द | तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
- 6-राधा पुत्री मुकन्द पत्नी संदीप जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों हाल निवासी  
कोक सिंह का पुरा खौडोली तहसील व जिला मुरैना म0प्र0
- 7-कल्लो पुत्री मुकन्द | पुत्रीगण मुकन्द जातिगण ठाकुर निवासीगण ग्राम
- 8-ज्योति पुत्री मुकन्द | तसीमों तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
- 9-भूदेवी पत्नी मोहनसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों तह0सैपऊ जिला धौ0
- 10-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तामील जरिये शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया  
शाखा सैपऊ जिला धौलपुर
- 11-तहसीलदार सैपऊ
- 12-ग्राम पंचायत तसीमों जरिय सरपंच ग्राम पंचायत तसीमों तहसील सैपऊ

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम  
एवम आधीन धारा 232 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकगण :-

- (- प्रार्थी की ओर से - श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट  
अप्रार्थी सं01लगा06, 8,9की ओर से - श्री शरीफ खान एडवोकेट  
अप्रार्थी सं011 की ओर से - श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभि0

(आर0 के0 जायसवाल)  
जिला कलक्टर, धौलपुर



(2)

न्या० जिला कलक्टर धौलपुर  
वमुक: रघुराजसिंह बनाम राजवीर वगैरा  
रैफरेन्स संख्या 59/2021

निर्णय

दिनांक 13.07.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 एवं आधीन धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि इस प्रार्थना पत्र में उक्त विवादित खसरा नम्बर 2130/2922 रकवा 03 बीधा 12 विस्वा बांके ग्राम तसीमों खसरा नम्बर 2130 रकवा 187 बीधा 06 विस्वा बांके ग्राम तसीमों का अंश (पार्ट) है अर्थात् 2130 में से बना है। खसरा नम्बर 2130 रकवा 187 बीधा 06 विस्वा गैर मुम्किन चारागाह भूमि थी तथा जिस पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार दिया जाना तथा जिसमें से नियमन एवं आवंटन किया जाना विधि द्वारा अपवर्जित था। खसरा नम्बर 2130 को विधिवत रूप से किस्म परिवर्तन किये बिना ग्राम पंचायत तसीमों द्वारा अवैध रूप से किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण संख्या 323 ग्राम तसीमों पारित कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था तथा ना ही किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। ग्राम पंचायत तसीमों द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 499 ग्राम तसीमों द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 8 के पूर्वज बंगाली पुत्र राजधर जाति ठाकुर निवासी ग्राम तसीमों के पक्ष में अवैध रूप से नियमन के आधार पर गैरखातेदारी का नामान्तकरण आदेश पारित कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को आवंटन व नियमन के आधार पर गैरखातेदारी का नामान्तकरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था लिहाजा नामान्तकरण संख्या 499 विधि विरुद्ध है। बंगाली पुत्र राजधर का निधन हो चुका है। बंगाली के वारिस एवं उत्तराधिकारीगण पुत्रगण श्यामबावू मुकन्द तथा राजवीर है तथा बंगाली की पत्नी गुडडी का भी निधन हो चुका है, बंगाली के पुत्र श्यामबावू का निधन हो चुका है, श्यामबावू के वारिस अप्रार्थी संख्या 2 व 3 है तथा मुकन्द का निधन हो चुका है, मुकन्द के वारिस अप्रार्थी संख्या 4 लगा० 8 है। बंगाली के निधनोपरान्त अवैध इन्द्राजात की आड में अप्रार्थी संख्या 1 लगा० 3 ने तथा स्व० मुकन्द ने अपने पक्ष में अवैध रूप से विरासतन खातेदारी इन्द्राजात अंकित करवा लिये है तथा अप्रार्थी संख्या 9 के पक्ष में अवैध रूप से 1/4 भाग का अन्तरण कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 2130/2922 रकवा 03 बीधा 12 विस्वा बांके ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ के नामान्तकरण संख्या 499 के सम्बन्ध में समुचित आदेशार्थ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 49 सम्बत 2070 से 2073, नकल नामान्तकरण संख्या 499, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 629 सम्बत 2033 से 2036, नकल नामान्तकरण संख्या 323 सम्बत 2033 से 2036 ग्राम तसीमों तहसील सैपऊ पेश की है।

(आरो के जायसदारी  
न्याय कलक्टर धौलपुर)

(3)

ज्या0 जिला कलक्टर धौलपुर  
वमुक: रघुराजसिंह बनाम राजवीर वगैरा  
रेफरेन्स संख्या 69/2021

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्जिय नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या-7 बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं होने पर उसाके विरुद्ध दिनांक 19.12.2018 को तथा अप्रार्थी संख्या 10 व 12 के विरुद्ध दिनांक 30.8.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या-11 की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये उनकी ओर से कोई जबाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या-1 लगा0 6, 8 व 9 की ओर से श्री शरीफ खान एडवोकेट ने बकालतनामा पेश कर उक्त अप्रार्थीगण की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया जिसमें उन्होंने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये जबाब में कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2130/2022 नियमन के समय 3 बीघा 12 बिसवा सिवायबक भूमि थी तथा उसाका विधि की प्रकिया अपनाते हुये नियमन किया गया। आज से करीब 42-43 वर्ष पूर्व विवादित आराजी किरम सिवायबक का नियमन बंगाली सिंह के हक में किया गया तथा श्रीमान एडीएम साहव धौलपुर द्वारा नियमन की पत्रावली पर सम्पूर्ण विचार व सुनवाई कर तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नियमन का आदेश किया गया उसाके तत्पश्चात बंगाली सिंह के हक में गैर खातेदारी दर्ज की गयी व नामान्तकरण फैसल किया गया। पिछले करीब 50 वर्षों से अधिक समय से उत्तरदातागण व उनके पूर्व पुरुष बंगाली सिंह विवादित आराजी पर नियमित रूप से काश्त करते आ रहे है और भूमि को काविल काश्त बनाया। यह कि 42 वर्ष से अधिक समय से उत्तरदातागण के परिवार की खातेदारी है व काश्त हो रही है ऐसी रिथति में कोई भी रेफरेन्स की कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत लागू नहीं होती। इतने लम्बे समय की खातेदारी को रेफरेन्स के द्वारा चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बावत रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की है। अप्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दरतावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है।

वहस अंतिम विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी गैर मुमकिन चारागाह भूमि थी जिस पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार दिया जाना नियमन एवं आवंटन किया जाना विधि द्वारा अपवर्जित था। विवादित आराजी को विधिवत रूप से किरम परिवर्तन किये बिना ग्राम पंचायत तसीमों द्वारा अवैध रूप से किरम परिवर्तन का नामान्तकरण संख्या 323 पारित कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को किरम परिवर्तन का नामान्तकरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था तथा ना ही किरम परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। ग्राम पंचायत तसीमों द्वारा नामान्तकरण संख्या 499 प्रार्थी संख्या 1 लगा0 8 के पूर्वज बंगाली के पक्ष में अवैध रूप से नियमन के आधार पर गैरखातेदारी का नामान्तकरण आदेश पारित कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को आवंटन व नियमन के आधार पर

(आर0 के0 जायसवाल)  
जिला कलक्टर, धौलपुर

(4)

न्याय जिला कलक्टर धौलपुर  
वमुक: रघुराजसिंह बनाम राजवीर वगैरा  
रैफरेन्स संख्या 59/2021

गैरखातेदारी का नामान्तकरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था लिहाजा नामान्तकरण संख्या 499 विधि विरुद्ध है। ऐसे गलत आदेशों इन्द्राजातों को कभी भी रैफरेन्स के माध्यम से निरस्त कराया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेन्स रवीकार फरमाया जावे।

अप्राथीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्रों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी नियमन के समय सिवायचक भूमि थी तथा उसका विधि की प्रकिया अपनाते हुये नियमन किया गया। दिनांक 1.6.1972 को किस्म परिवर्तन का आदेश जिला कलक्टर के द्वारा दिये गये जो नामान्तकरण में दर्ज है। अप्राथीगण के पूर्व पुरुष के कब्जे के आधार पर 1977 में विवादित आराजी नियमन की गई। श्रीमान एडीएम साहव धौलपुर द्वारा नियमन की पत्रावली पर सम्पूर्ण विचार व सुनवाई कर तथा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत नियमन का आदेश किया गया है। पिछले करीब 50 वर्षों से अधिक समय से उत्तरदातागण व उनके पूर्व पुरुष बंगाली सिंह विवादित आराजी पर नियमित रूप से कास्त करते आ रहे हैं 42 वर्ष से अधिक समय से उत्तरदातागण के परिवार की खातेदारी है ऐसी स्थिति में कोई भी रैफरेन्स की कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत लागू नहीं होती। इतने लम्बे समय की खातेदारी को रैफरेन्स के द्वारा चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रैफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी के अभिभाषक का मुख्य रूप से यह कथन है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन चारागाह भूमि थी जिस पर धारा 16 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार दिया जाना, नियमन एवं आवंटन किया जाना विधि द्वारा अपवर्जित था। विवादित आराजी को विधिवत रूप से किस्म परिवर्तन किये बिना ग्राम पंचायत द्वारा अवैध रूप से किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण संख्या 323 पारित कर दिया जबकि ग्राम पंचायत को किस्म परिवर्तन का नामान्तकरण आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था तथा ना ही किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। हमने पत्रावली पर उपलब्ध नकल नामान्तकरण संख्या 323 का अवलोकन किया पूर्व में उक्त विवादित आराजी चारागाह थी परन्तु उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14-16 में जिलाधीश भरतपुर के अंकित आदेश दिनांक 1.6.1972 से उक्त विवादित आराजी की किस्म परिवर्तन चारागाह से सिवायचक करने के आदेश से उक्त नामान्तकरण संख्या 323 खोला गया है। अप्राथी का कथन है कि कब्जे के आधार पर उक्त विवादित आराजी 1977 में अप्राथीगण के पूर्व पुरुष को नियमन की गई। नामान्तकरण संख्या 499 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि एडी.एम. धौलपुर के आदेश से अप्राथी के

(आरो के० जागरवाल)  
जिला कलक्टर, धौलपुर

(5)

न्या० जिला कलक्टर धौलपुर  
वमुक: रघुराजसिंह बनाम राजवीर वगैरा  
रेफरेन्स संख्या 59/2021

पूर्व पुरुष को गैरखातेदार दर्ज कर नामान्तकरण खोला गया। वर्तमान में उक्त विवादित आराजी 42 वर्ष से अधिक समय से अप्रार्थीगण के परिवार की खातेदारी में है। इतने लम्बे समय की खातेदारी को रेफरेन्स के द्वारा चैलेन्ज नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रा०पत्र भी करीब 42 वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना एवं रेफरेन्स किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुभार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 13.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आर.के. जाधववाल)  
जिला कलक्टर, धौलपुर  
13/2

